प्रकाशन का गौरवाशाली 14वाँ वर्ष

दिव्य हिमगिरि

हिमालयी राज्यों की पहली साप्ताहिक पत्रिका

नज़र सब पर

वर्ष 14 | अंक 48 | मूल्य 15 रुपये | 20-26 अप्रैल, 2025

धामी सरकार देवभूमि के किसानों को बनाएगी 'मालामाल'

उत्तराखंड बोर्ड ने जारी किया रिजल्ट, 12वीं में अनुष्का, 10वीं में कमल और जतिन संयुक्त रूप से टॉपर

भाजपा में 'बड़े बदलाव' की तैयारी

EXPERIENCE HELI TOUR WITH

Himgiri
Aviation & Tourism

5N/6D TOUR

Chardham
YATRA BY HELICOPTOR

LIMITED SEATS ARE LEFT **BOOK NOW**

Contact for Reservation **8433456398, 9410353164**

Email: himgiritourism@gmail.com
6 Municipal Road, Opps. Bala hissar Academy, Dalanwala, Dehradun-248001 (UK)

वर्ष 14 | अंक 48

दिव्य हिमगिरि

20-26 अप्रैल, 2025

संपादक
कुँवर राज अस्थाना

वरिष्ठ संवाददाता
शंभूनाथ गौतम

ब्यूरो प्रमुख
मोनिका डबराल

विज्ञापन
पूनम आर्या

ग्राफिक डिजायनर
देव भट्ट

संवाददाता
हरिद्वार : डॉ. रजनीश गौतम
पौडी : रत्नमणि भट्ट
कोटद्वार : के.पी. बौंठियाल
रूद्रपुर : हेमचन्द्र बुडलाकोटी
चमोली : मुकेश रावत
रुड़की : श्रीगोपाल नारसन
नैनीताल : शीतल तिवारी
अल्मोड़ा : संजय कुमार अग्रवाल (एड.)
विकासनगर : अजय शर्मा
प्रसार : रमेश सिंह रावत

संपादकीय कार्यालय : 6, म्युनिसिपल रोड, बाला हिसार स्कूल के सामने, डालनवाला देहरादून (उत्तराखंड)
मोबाइल : +91 8433456398, 9410353164
Email: divyahimgiriddn@gmail.com

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं मुद्रक कुँवर बहादुर अस्थाना द्वारा सरस्वती प्रेस, 2, ग्रीन पार्क, निरंजनपुर, देहरादून से मुद्रित तथा 39/7 ई, ई. सी. रोड, (निकट मार्शल स्कूल सीनियर विंग) देहरादून-248001 उत्तराखण्ड से प्रकाशित।
संपादक: कुँवर बहादुर अस्थाना*

*(पीआरबी एक्ट के तहत प्रकाशित सामग्री के लिए उत्तरदायी)

संविधान के अनुच्छेद 142 पर मचा सियासी घमासान

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के न्यूक्लियर मिसाइल वाले बयान सियासी विवाद खड़ा हो गया है। धनखड़ ने गुरुवार को कहा था कि अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती। संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत कोर्ट को मिला विशेष अधिकार लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है। अब इस पर विपक्ष की तरफ से सियासी फायरिंग की जा रही है। कई तरह के बयान आ रहे हैं कुछ लोग उनके बयान को गलत और कुछ सही बता रहे हैं। सवाल ये है कि क्या उपराष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट पर ऐसा बयान देना चाहिए। इसे समझने से पहले संविधान के अनुच्छेद 142 को समझते हैं, जिसको लेकर उपराष्ट्रपति धनखड़ ने सवाल उठाए हैं। संविधान में अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को कुछ अपरिहार्य शक्तियां देता है। जिससे सुप्रीम कोर्ट पूर्ण न्याय सुनिश्चित कर सके, इसका मतलब है कि अगर कोर्ट को लगता है कि पूर्ण न्याय नहीं हो रहा है तो वो इस अनुच्छेद का इस्तेमाल कर सकता है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट किसी भी मामले में निर्देश, आदेश या फैसला दे सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट को किसी मामले में लगता है कि मौजूदा कानून से पूर्ण न्याय नहीं हो पा रहा, तो कोर्ट अपनी समझ से फैसला दे सकता है। कोर्ट इस शक्ति का इस्तेमाल तब ही करता है जब मौजूदा कानून किसी मामले में नाकाफी लगते हैं। हालांकि यहां ये साफ है कि अनुच्छेद 142 के तहत दिया गया सुप्रीम कोर्ट का फैसला संविधान का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए और संविधान की मूल भावना के अनुरूप ही हो। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले कुछ दिनों में कई बार अनुच्छेद 142 के तहत फैसले दिए हैं। चंडीगढ़ के मेयर चुनाव को रद्द करने का फैसला भी इसी के तहत लिया गया था। राज्यसभा के 6वें बैच के प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए धनखड़ ने आगे कहा कि 'हम ऐसी स्थिति नहीं रख सकते जहां आप भारत के राष्ट्रपति को निर्देश दें। उन्होंने कहा कि न्यायाधीशों ने जो वस्तुत: राष्ट्रपति को एक आदेश जारी किया वह एक परिदृश्य प्रस्तुत किया है कि यही देश का कानून होगा।' सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यपाल की तरफ से भेजे गए बिल पर राष्ट्रपति को तीन महीने के भीतर फैसला लेना होगा। दरअसल, 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल के मामले में ऐतिहासिक फैसला लिया था। कोर्ट ने कहा था कि राज्यपाल को विधानसभा की ओर से भेजे गए बिल पर एक महीने के भीतर फैसला लेना होगा। इसी फैसले के दौरान अदालत ने राज्यपालों की ओर से राष्ट्रपति को भेजे गए बिल पर भी स्थिति स्पष्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यपालों की ओर से भेजे गए बिल के मामले में राष्ट्रपति के पास पूर्ण वीटो या पॉकेट वीटो का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि राज्यपाल ने विधानसभा से पारित विधेयकों को संशोधनों के लिए लौटाया है और विधानसभा ने उन्हें पुन: पारित करके भेजा है तो वह उनको लंबित नहीं रख सकते और न ही राष्ट्रपति को भेजे जाने की दशा में उन्हें लंबित रखा जा सकता है। ऐसे विधेयकों को पास मान लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यहा कि राष्ट्रपति के फैसले की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है और किसी भी बिल की संवैधानिकता का फैसला न्यायपालिका करेगी। यानि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में स्पष्ट कर दिया कि कोई विधेयक संवैधानिक है या नहीं यह फैसला करने का अधिकार केवल न्यायपालिका का है। राष्ट्रपति चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से किसी भी बिल पर सलाह ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट के ऐसा कहने में कार्यपालिका को असहज नहीं होना चाहिए। दरअसल राज्यपालों के साथ केवल उन्हीं राज्यों में दिक्कत पेश आ रही है जहां भाजपा की सरकार नहीं है।

कुँवर राज अस्थाना

भाजपा में 'बड़े बदलाव' की तैयारी

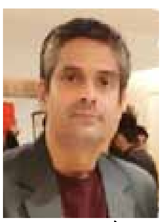

शंभू नाथ गौतम
वरिष्ठ पत्रकार

वर्तमान भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल जनवरी 2023 में ही खत्म हो गया था। सवा दो साल बाद भी पार्टी अपने नए अध्यक्ष का नाम घोषित नहीं कर सकी। पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को अपने नए मुखिया का इंतजार है। दो वर्षों में पार्टी के कई नेताओं के नाम अध्यक्ष की रेस में सुर्खियों में तो रहे लेकिन ऐनमौके पर हाईकमान फैसला नहीं ले सका। पहले लोकसभा फिर हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, झारखंड और दिल्ली विधानसभा चुनाव के चलते भाजपा अध्यक्ष का नाम घोषित नहीं कर सकी। वहीं दूसरी ओर आरएसएस और भाजपा के बीच नए अध्यक्ष को लेकर एक राय भी नहीं बन पाई। राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ कई राज्यों में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव भी नहीं हो सके। अब भाजपा के शीर्ष स्तर पर गहमागहमी देखी गई। पिछले दिनों दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर बड़ी बैठक हुई, जिसमें अमित शाह, राजनाथ सिंह और बीएल संतोष जैसे पार्टी और आरएसएस के बड़े नेता शामिल हुए। लंबे इंतजार के बाद पार्टी अब सस्पेंस खत्म करने जा रही है। भाजपा अब बड़े बदलाव के लिए तैयार है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया 20 अप्रैल के बाद शुरू हो सकती है।

करीब दो दशक के लंबे इंतजार के बाद भारतीय जनता पार्टी में पहली बार ऐसा हुआ है कि हाईकमान अपने नए अध्यक्ष का फैसला नहीं कर सका? यह आश्चर्य है कि वर्तमान भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल जनवरी 2023 में ही खत्म हो गया था। सवा दो साल बाद भी पार्टी अपने नए अध्यक्ष का नाम घोषित नहीं कर सकी। पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को अपने नए मुखिया का इंतजार है। पिछले दो वर्षों में पार्टी के कई नेताओं के नाम अध्यक्ष की रेस में सुर्खियों में तो रहे लेकिन ऐनमौके पर हाईकमान फैसला नहीं ले सका। पहले लोकसभा चुनाव फिर हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, झारखंड और दिल्ली विधानसभा चुनाव के चलते भाजपा अध्यक्ष का नाम घोषित नहीं कर सकी। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और भाजपा के बीच नए अध्यक्ष को लेकर एक राय नहीं बन पाई। राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ कई राज्यों में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव भी नहीं हो सके । लंबे इंतजार के बाद पार्टी अब सस्पेंस खत्म करने जा रही है। अब भारतीय जनता पार्टी बड़े बदलाव के लिए तैयार है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया 20 अप्रैल के बाद शुरू हो सकती है। इसको लेकर पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में भाजपा के शीर्ष स्तर पर काफी गहमागहमी देखी गई। बुधवार को राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें अमित शाह, राजनाथ सिंह और बी एल संतोष जैसे पार्टी और आरएसएस के बड़े नेता शामिल हुए। इस बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगामी चुनाव पर चर्चा हुई। चुनाव की घोषणा एक सप्ताह के भीतर की जा सकती है। बैठक में कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के अध्यक्षों के नामों पर चर्चा हुई है। अगले कुछ दिनों में करीब आधा दर्जन राज्यों के अध्यक्षों की घोषणा हो सकती है। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया

जेपी नड्डा जनवरी 2020 से भाजपा के अध्यक्ष बने हुए है

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यकाल के आखिरी कुछ दिन बचे हैं। इस महीने बीजेपी की कमान नए हाथों में जा सकती है। फिलहाल प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया जारी है। इसके ठीक बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। पार्टी के नियम के अनुसार बीजेपी अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का होता है। एक व्यक्ति 2 बार से अधिक पार्टी का अध्यक्ष नहीं बन सकता। ऐसे में अब पार्टी के नए अध्यक्ष को 12 अहम चुनाव अपने कार्यकाल में कराने होंगे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव जनवरी में होना था, लेकिन अप्रैल आधा बीत जाने के बाद भी नहीं हो सका है। जेपी नढा जनवरी, 2020 से राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। पार्टी संविधान के मुताबिक उनका कार्यकाल जनवरी, 2023 में खत्म हो गया, लेकिन लोकसभा चुनाव समेत कई बड़े चुनावों के मद्देनजर उनका कार्यकाल आगे बढ़ा दिया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव जनवरी में होना था। हालांकि, अप्रैल आधा बीत जाने के बाद भी यह लंबित है। जनवरी 2020 से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे जेपी नड्डा ने अगले नेतृत्व चरण के लिए सुचारू संक्रमण और उचित तैयारी सुनिश्चित करने के लिए अपना कार्यकाल तीन साल की सीमा से आगे बढ़ाया था। भाजपा संविधान के अनुसार, राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल आम तौर पर तीन साल का होता है, जिसे पार्टी के भीतर आम सहमति से चुना जाता है।

कभी भी शुरू हो सकती है। बैठक में राष्ट्रीय नेतृत्व पर विचार-विमर्श के अलावा राज्य स्तर पर संगठनात्मक बदलावों पर भी चर्चा हुई। जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा 2029 का लोकसभा चुनाव उसी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। ऐसे में जरूरी है कि कहीं से यह संदेश न जाए कि संगठन में एक वर्ग की नहीं सुनी जाती या फैसला जबरन थोपा गया है। बीते दस सालों में विपक्ष लगातार यह नैरेटिव गढ़ने का प्रयास कर रहा है। वहीं संघ इस पर सहमति चाहता है कि भाजपा सहित सभी आनुषांगिक संगठनों में विचारधारा के प्रति समर्पित युवाओं को तरजीह मिले। वैचारिक रूप से अलग होने के बावजूद विचारधारा और संगठन के प्रति समर्पण जिम्मेदारी देने का एकमात्र पैमाना हो। पहली कतार के नेता ऐसा फ्रेम वर्क दें, जिससे कार्यकर्ता भविष्य में विकल्प बन सकें। पार्टी को ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो भाजपा के विशाल संगठनात्मक ढांचे को कुशलता से संभाल सके, संघ की विचारधारा से मेल खाता हो और मोदी-शाह की जोड़ी का भरोसेमंद हो। साथ ही, वह विपक्ष के नैरेटिव की प्रभावी काट भी पेश कर सके।

भाजपा के संविधान के अनुसार, राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से पहले कम से कम 50 प्रतिशत राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति होनी जरूरी है। अब तक 14 राज्यों में नए अध्यक्ष चुने जा चुके हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा और पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्यों में यह पद अभी खाली है। इस हफ्ते इन राज्यों के लिए नामों का एलान हो सकता है।

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में कई नाम दौड़ में, पार्टी फिर चौंका सकती है

अप्रैल के आखिर में या फिर मई के पहले हफ्ते में भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा कर दी जाएगी। पार्टी के अध्यक्ष की रेस में कई नाम आगे चल रहे हैं। लेकिन अंतिम मुहर अभी तक नहीं लग सकी है। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर अध्यक्ष के रूप में नया चेहरा लाकर सभी को चौंका सकती है। भाजपा नेतृत्व अगले पार्टी अध्यक्ष के चयन पर चल रहे गतिरोध को खत्म करने के लिए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के साथ भी नए सिरे से बातचीत की योजना बना रही है। संघ प्रमुख मोहन भागवत और महासचिव दत्तात्रेय होसबोले सहित आरएसएस का शीर्ष नेतृत्व अगले हफ्ते दिल्ली में होगा। पीएम नरेंद्र मोदी भी 30 मार्च को आरएसएस मुख्यालय मे मोहन भागवत से मिले थे लेकिन भाजपा अध्यक्ष पर आम सहमति बनाने में किल रहे। इसलिए अब नए सिरे से बातचीत होगी। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर का नाम भी अध्यक्ष की रेस में है। इसके अलावा मोदी सरकार में ही मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव के नामों की भी चर्चा जोरों पर है। कहा जा रहा है कि इन तीन नेताओं में से किसी एक को अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जा सकती है। वहीं शिवराज सिंह चौहान 6 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। 4 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। मुख्यमंत्री रहते हुए लाडली बहना योजना शुरू की, जो विधानसभा चुनाव में गेमचेंजर साबित हुई। ये योजना दूसरे राज्यों के लिए रोल मॉडल बन गई। सुनील बंसल के पास 2014 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी और फिर 2017 में प्रभारी की जिम्मेदारी रहते हुए पार्टी को कामयाबी दिलाई। इसके अलावा ओडिशा, बंगाल और तेलंगाना के प्रभारी के रूप में मिली कामयाबी भी बड़ा प्लस पॉइंट है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का नाम चल रहा है। प्रहलाद जोशी को पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। कर्नाटक की धारवाड़ लोकसभा सीट से सांसद जोशी अभी मोदी सरकार में कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और रिन्यूएबल एनर्जी मंत्री हैं। प्रहलाद जोशी आरएसएस से होते हुए भाजपा सरकार में इतने बड़े पद तक पहुंचे हैं।

बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का नाम सबसे आगे चल रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि सीतारमण साउथ से आती हैं। तमिलनाडु में इस समय परिसीमन का मामला गरमाया हुआ है। अध्यक्ष पर फैसला लेने से पहले आरएसएस की सलाह भी ली जाएगी। वहीं उससे पहले यूपी, बंगाल, आंध्र प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में अध्यक्ष का फैसला भी लिया जाएगा। तभी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बारे में कुछ भी जहां नहीं जा सकता है राज्यों के मुख्यमंत्री को लेकर अभी तक हाईकमान चौंकाने वाले नामों का एलान करता रहा है। हो सकता है भाजपा अध्यक्ष के नाम में भी फिर चौंका सकती है। फिलहाल नया अध्यक्ष कौन बनेगा, सस्पेंस कायम है। लेकिन जल्द ही पार्टी अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर देगी।

उत्तराखंड बोर्ड ने जारी किया रिजल्ट, 12वीं में अनुष्का, 10वीं में कमल और जतिन संयुक्त रूप से टॉपर

उत्तराखंड बोर्ड ने 10वीं और 12वीं परीक्षाओं का रिजल्ट किया जारी। इस बार उत्तराखंड बोर्ड ने रिजल्ट पिछले वर्षों की अपेक्षा सबसे जल्दी जारी किया। हाईस्कूल का कुल पास फीसदी 90.77 फीसदी रहा। इसमें 93.25 प्रतिशत छात्राएं जबकि 88. 20 प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। 12वीं का टोटल पास फीसदी 83.23 फीसदी रहा है। इसमें 86.20 फीसदी छात्राएं उत्तीर्ण हुई जबकि 83.23 फीसदी छात्र पास हुए। 12वीं में राजकीय इंटर कॉलेज भदासी देहरादून की छात्रा अनुष्का राणा ने इंटर में टॉप किया है। हाईस्कूल में बागेश्वर के कमल सिंह चौहान और नैनीताल के जतिन जोशी ने 99.20 अंक पाकर संयुक्त रूप से टॉप किया है। दोनों छात्रों ने 500 में से 496 अंक प्राप्त किए हैं। धामी सरकार ने एलान किया है कि जिन स्टूडेंट्स के 70 फीसदी से ऊपर मार्क्स हैं उन्हें सरकार की ओर से लैपटॉप और एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा।

उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (यूबीएसई) ने शनिवार 19 अप्रैल को कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। बोर्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से परिणाम की घोषणा की। इस बार उत्तराखंड बोर्ड ने 10वीं और 12वीं परीक्षा का रिजल्ट पिछले वर्षों की अपेक्षा सबसे जल्दी जारी किया है। इससे पहले बिहार सरकार बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट जारी कर चुकी है।

हाईस्कूल का कुल पास फीसदी 90.77 फीसदी रहा। इसमें 93.25 प्रतिशत छात्राएं जबकि 88.20 प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। 12वीं का टोटल पास फीसदी 83.23 फीसदी रहा है। इसमें 86.20 फीसदी छात्राएं उत्तीण र् हुई जबकि 83.23 फीसदी छात्र पास हुए। यूके बोर्ड इंटरमीडिएट 12वीं में राजकीय इंटर कॉलेज भदासी देहरादून की छात्रा अनुष्का राणा ने इंटर में टॉप किया है। वहीं 10वीं में दो छात्रों ने टॉप किया है। इस साल के टॉपर कमल सिंह चौहान और जतिन जोशी हैं, दोनों ने 500 में से 496 अंक प्राप्त किए हैं। 12वीं में देहरादून की अनुष्का राणा ने टॉप किया है। अनुष्का ने 98.60 फीसदी अंक हासिल कर पहला स्थान हासिल किया है। अनुष्का राणा ने 500 में से 493 अंक हासिल किए हैं। 12वीं में केशव भट्ट ने दूसरा स्थान पाया है। केशव ने 500 में 489 नंबर पाए हैं। आयुष सिंह रावत ने तीसरा स्थान हासिल किया है। आयुष ने 500 में 484 अंक हासिल किए हैं। 96.80 फीसदी नंबर हासिल किए हैं। वहीं 10वीं में कुल 90.77 फीसदी छात्र-छात्राएं पास हुए।

हाईस्कूल में बागेश्वर के कमल सिंह चौहान और नैनीताल के जतिन जोशी ने 99.20 अंक पाकर संयुक्त रूप से टॉप किया है। दोनों छात्रों ने 500 में से 496 अंक प्राप्त किए हैं। टिहरी की कनक लता ने 495 अंक पाकर 99% के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है। रुद्रप्रयाग की प्रिया और दीपा जोशी 98.80 अंक के साथ तीसरे नंबर पर रही। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले सभी छात्रों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि आप लोग इसी तरह सफलता के नए सोपान छूएं, ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है। मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले सभी छात्रों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आप लोग इसी तरह सफलता के नए सोपान छूएं, ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है।

प्रदेश सरकार की ओर से 70 फीसदी से ऊपर मार्क्स लाने वाले विद्यार्थियों को मिलेगा लैपटॉप

उत्तराखंड बोर्ड की ओर से टॉपर्स के लिए एक बड़ी घोषणा की गई है। बोर्ड ने एलान किया है कि जिन स्टूडेंट्स के 70 फीसदी से ऊपर मार्क्स हैं उन्हें सरकार की ओर से लैपटॉप और एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। हाइस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में 70 फीसदी अंक हासिल करने वाले छात्रा छात्राओं को लैपटॉप दिया जाएगा। 10वीं और 12वीं की परीक्षा 21 फरवरी से शुरू होकर 11 मार्च तक आयोजित की गई थी। 10वीं में 109,859 ने परीक्षा दी थी। 99,725 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। 12वीं में 1,06,345 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए। 88518 विद्यार्थियों उत्तीर्ण हुए। छात्रों ने 1245 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा दी थी। 21 मार्च से 4500 शिक्षकों ने 11 लाख उत्तर पुस्तिकाओं की जांच की थी। अब परिणाम जारी हुआ। बीते साल 2024 के टॉपर्स की बात करें तो कक्षा 12वीं में टॉपर दो छात्रों, पीयूष खोलिया और कंचन जोशी ने साझा किया, दोनों ने 500 में से 488 अंक प्राप्त किए और 97.60 प्रतिशत अंक प्राप्त किए। कक्षा 10 में, प्रियांशी रावत टॉपर राइख, 500 से 500 का पूर्ण स्कोर प्राप्त हुआ। पिछले साल उत्तराखंड बोर्ड की ओर से 2024 में जारी आधिकारिक जानकारी के अनुसार, यूबीएसई कक्षा 10 और 12 परीक्षा परिणामों में कुल पास प्रतिशत क्रमश: 89.14 और 82.63 प्रतिशत था। इससे पहले 2023 में कक्षा 10 में पास प्रतिशत 85.17 प्रतिशत था और कक्षा 12 में यह 80.98% था। लड़कियों ने कक्षा 10 और 12 में दोनों में लड़कों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया था।

चारधाम यात्रा के लिए 28 अप्रैल से शुरू होंगे ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन

चार धाम यात्रा को लेकर धामी सरकार की तैयारी अंतिम चरणों में है। 30 अप्रैल से शुरू होने वाली यात्रा के लिए हरिद्वार, ऋषिकेश, विकास नगर और हरबर्टपुर में 65 ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन काउंटर खोले जाएंगे। इसके अलावा यात्रा रूट पर भी अलग-अलग जगह रजिस्ट्रेशन काउंटर खोलने की तैयारी है। इस बार ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की संख्या बढ़ाई गई है। अभी तक 18 लाख से अधिक तीर्थयात्री ऑनलाइन पंजीकरण करा चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा- चार धाम यात्रा हम सबके लिए महत्वपूर्ण है। यात्रा में देश और विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। उनको लिए सुरक्षित यात्रा करना हम सब का दायित्व बनता है। इसलिए यात्रा को लेकर सभी तैयारी पूरी कर ली गई है।

10 दिन बाद 30 अप्रैल को उत्तराखंड में चार धाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। चार धाम यात्रा को लेकर धामी सरकार की तैयारी अंतिम चरणों में है। अभी तक चार धाम यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। अब ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी शुरू होने जा रहे हैं। पर्यटन विभाग ने इस वर्ष 20 मार्च से आधार कार्ड आधारित ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। विभाग के मुताबिक अब तक 18 लाख से अधिक तीर्थयात्री विभिन्न तिथियों के लिए अपना पंजीकरण करा चुके हैं। इनमें से 16,741 विदेशी यात्रियों ने भी ऑनलाइन पंजीकरण करवाया है। 28 अप्रैल से यात्रा के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो जाएंगे। हरिद्वार, ऋषिकेश, विकास नगर और हरबर्टपुर में 65 ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन काउंटर खोले जाएंगे। इसके अलावा यात्रा रूट पर भी अलग-अलग जगह रजिस्ट्रेशन काउंटर खोलने की तैयारी है। इस बार ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की संख्या बढ़ाई गई है। ऑनलाइन पंजीकरण नहीं कराने वाले यात्री 28 अप्रैल से ऑफलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। इस साल सरकार ने तय किया है कि समूह में यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं का ठहरने वाले स्थान पर ही पंजीकरण कराया जाएगा। इसके लिए ऋषिकेश में 30, हरिद्वार में 20 रजिस्ट्रेशन काउंटर खोले जाएंगे जबकि विकास नगर और हरबर्टपुर 15 पंजीकरण काउंटर खोले जाएंगे।

चार धाम यात्रा के लिए सभी तैयारियां पूरी: सीएम धामी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चार धाम यात्रा हम सबके लिए महत्वपूर्ण है। यात्रा में देश और विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। उनको लिए सुरक्षित यात्रा करना हम सब का दायित्व बनता है। इसलिए यात्रा को लेकर सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। उन्होंने की यात्रा को संचालित करने में सबकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए सभी विभाग यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। पिछले सालों की तरह इस साल भी हमारी यात्रा चारों धाम और देवी देवताओं की कृपा से सरल और सुरक्षित होगी। पर्यटन विभाग ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे यात्रा पर निकलने से पहले अपना पंजीकरण सुनिश्चित करें और यात्रा के दौरान जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें। विभाग ने यात्रियों को अपने साथ आवश्यक दवाइयां, गर्म कपड़े और आधार कार्ड सहित अन्य पहचान पत्र रखने की सलाह दी है। चारधाम यात्रा के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए रूटों पर जगह-जगह स्पष्ट साइन बोर्ड लगाए जा रहे हैं। इससे श्रद्धालुओं को अपने गंतव्य तक पहुंचने में सुविधा होगी और वे रास्ता भटकने से बच सकेंगे। साथ ही मौसम और स्वास्थ्य की स्थिति को ध्यान में रखते हुए यात्रा की योजना बनाने को कहा गया है। चारधाम यात्रा 2025 की तैयारियों के साथ सरकार का लक्ष्य है कि श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुविधाजनक और यादगार अनुभव प्रदान किया जा सके।

चार धाम यात्रा के लिए राज्य सरकार ने स्थापित किए कंट्रोल रूम

चार धाम यात्रा के लिए अभी तक लगभग 17,853 लोग कंट्रोल रूम से संपर्क कर चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चार धाम यात्रा के लिए देश भर के यात्रियों में उत्साह है। देवभूमि उत्तराखण्ड सभी यात्रियों के स्वागत के लिए तैयार है। यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु राज्य

सरकार कृत संकल्प है। सभी के सहयोग से बेहतर यात्रा संचालन सुनिश्चित किया जाएगा। चार धाम यात्रा को सुरक्षित, सुगम और सुव्यवस्थित बनाने हेतु मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर पशुपालन विभाग घोड़े-खच्चरों के स्वास्थ्य परीक्षण में जुट गया है। इसी क्रम में पशुपालन विभाग की रोग अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा श्रीनगर यात्रा में आने वाले घोड़े-खच्चरों के रक्त सीरम की जांच की जा रही है। प्रयोगशाला में ग्लैंडर्स और इक्वाइन इन्फ्लूएंजा (ईआई) या हॉर्स फ्लू संक्रमण की जांच हो रही है। अब तक यहां पांच हजार से ऊपर सैंपल जांच के लिए पहुंच चुके हैं। यमुनोत्री, केदारनाथ और हेमकुंट साहिब की यात्रा में तीर्थयात्रियों के आवागमन और सामान ले जाने के मुख्य साधन घोड़े-खच्चर हैं। भारी संख्या में विभिन्न स्थानों से घोड़े-खच्चर यात्रा के दौरान यहां पहुंचते हैं। आंकड़ों के मुताबिक, हर साल चार धाम यात्रा के दौरान केदारनाथ धाम में लगभग आठ हजार, यमुनोत्री धाम में तीन हजार और हेमकुंड साहिब की यात्रा में एक हजार घोड़े-खच्चर आते हैं। ऐसे में उनमें आपस में संक्रमण का खतरा बना रहता है। प्रमुख पड़ावों में पशुपालन विभाग की ओर से पशुओं की फिटनेस देखी जाती है। कुछ वर्ष पूर्व घोड़े-खच्चरों में ग्लैंडर्स और इक्वाइन इन्फ्लूएंजा सामने आए हैं। ग्लैंडर्स संक्रमण से ग्रसित पशु को आइसोलेट (पृथक) करना व यूथनाइज (इच्छा मृत्यु) मजबूरी हो जाती है, ताकि अन्य पशुओं में यह संक्रमण न फैले। पशुपालन विभाग विभिन्न स्थानों पर स्थापित बैरियर्स पर घोड़े-खच्चरों के रक्त के नमूने ले रहा है। इन नमूनों को जांच के लिए पौड़ी जिले के श्रीनगर स्थित रोग अनुसंधान प्रयोगशाला भेजा जा रहा है।

2 मई को तुंगनाथ और 21 मदमहेश्वर मंदिरों के कपाट खोले जाएंगे

उत्तराखंड में चार धामों के साथ ही पंच केदारों में से दो मंदिरों के कपाट भी श्रद्धालुओं के लिए खोले जाने की तिथि घोषित कर दी गई है। पंच केदारों में प्रतिष्ठित द्वितीय केदार श्री मदमहेश्वर मंदिर के कपाट 21 मई को कर्क लग्न में साढ़े ग्यारह बजे खोले जायेंगे, जबकि इससे पहले दो मई को तृतीय केदार श्री तुंगनाथ के कपाट मिथुन लग्न में सवा दस बजे श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोलने के लिए तिथि घोषित की गई। श्री ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ और श्री मर्करेटेश्वर मंदिर मक्कूमठ से राज्यमंत्री चंडी प्रसाद भट्ट और बीकेटीसी मुख्य कार्याधिकारी विजय प्रसाद थपलियाल की उपस्थिति में कपाट खुलने की तिथियां घोषित की गई। मंदिर समिति के आचार्य वेदपाठियों ने पंचाग गणना के बाद पंचकेदारों में प्रतिष्ठित द्वितीय केदार श्री मद्महेश्वर मंदिर के कपाट खुलने की तिथि की घोषण ा की गई। तुंगनाथ की चल विग्रह डोली 30 अप्रैल को श्री मर्करेटेश्वर मंदिर मक्कूमठ से भूतनाथ मंदिर में आयेगी। इसी दिन 30 अप्रैल को भूतनाथ मंदिर में प्रवास रहेगा। 1 मई को तुंगनाथ जी की चल विग्रह डोली चोपता प्रवास के लिए पहुंचेगी। 2 मई सुबह भगवान तुंगनाथ जी की चल विग्रह डोली चोपता से श्री तुंगनाथ पहुंचेगी। 2 मई को 10:15 श्री तुंगनाथ मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए दर्शनार्थ खुलेंगे। इसी तरह 18 मई को भगवान मदमहेश्वर की चल विग्रह उत्सव मूर्तियां ओंकारेश्वर मन्दिर से सभा मण्डप मे विराजमान होगी। 19 मई को भगवान मदमहेश्वर की चल विग्रह उत्सव डोली शीतकालीन गद्दी स्थल ओकारेश्वर से रवाना होगी। विभिन्न यात्रा पड़ावों से होते हुए हुए 21 मई को मदमहेश्वर धाम पहुंचेगी। भगवान मदमहेश्वर की चल विग्रह उत्सव डोली के धाम पहुंचने पर मदमहेश्वर धाम के कपाट वेद ऋचाओ के साथ ग्रीष्मकाल के लिए खोल दिये जायेंगे।

समुद्र तल से करीब 3690 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है तुंगनाथ मंदिर

रुद्रप्रयाग में समुद्र तल से करीब 3690 मीटर की ऊंचाई पर स्थित तुंगनाथ मंदिर में भोलेनाथ की भुजाओं की पूजा होती है। यहां भगवान शिव के दर्शन इतनी आसानी से नहीं होते हैं बल्कि यहां जाने के लिए करीब तीन किलोमीटर की ट्रेकिंग करनी पड़ती है। यह मंदिर महाभारत काल का बताया जाता है, जिसे पांडवों ने बनवाया था ताकि भगवान शंकर उनसे प्रसन्न हो सकें। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि मां पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए यहीं तपस्या की थी। 'तुंग' का मतलब हाथ और 'नाथ' का मतलब भगवान होता है। श्री मद्महेश्वर और श्री तुंगनाथ मंदिर के कपाट खुलने की तिथि की घोषणा से श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल है। हर साल हजारों की संख्या में श्रद्धालु इन पवित्र धामों की यात्रा करते हैं। इस बार भी कपाट खुलने के शुभ अवसर पर बड़ी संख्या में भक्तों के पहुंचने की संभावना है। प्रशासन द्वारा यात्रा मार्गों की तैयारी और सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

धामी सरकार का ठोस एक्शन प्लान: डेंगू-चिकनगुनिया के खिलाफ राज्यभर में सभी विभाग मैदान में बहुस्तरीय अभियान शुरू

डेंगू-चिकनगुनिया से जंग में हर नागरिक की भागीदारी ज़रूरी: डॉ. आर. राजेश कुमार

डेंगू एवं चिकनगुनिया जैसे घातक संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने एक ठोस और समग्र कार्ययोजना लागू कर दी है। गर्मी और बरसात के मौसम में डेंगू व चिकनगुनिया फैलने की संभावना अधिक रहती है। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य के सभी जिलों में इन रोगों से निपटने के लिए अंतरविभागीय समन्वय, सक्रिय चिकित्सा व्यवस्थाएं, जनजागरूकता, निगरानी और फील्ड एक्शन के लिए व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इस संपूर्ण अभियान में नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग, जल निगम, शिक्षा विभाग, ग्राम्य विकास, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग सहित कई विभागों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। स्वास्थ्य सचिव डॉ आर राजेश कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व स्वास्थ्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत के दिशा- निर्देशों पर स्वास्थ्य विभाग सहित सभी विभागों को अर्लट कर दिया गया है। विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी गई है। स्वास्थ्य सचिव ने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि डेंगू-चिकनगुनिया से जंग में हर नागरिक की भागीदारी जरूरी है।

स्वच्छता, लार्वा नियंत्रण और जन जागरूकता पर विशेष बल: स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने बताया कि, 'डेंगू व चिकनगुनिया जैसे मच्छरजनित रोगों की रोकथाम का पहला कदम स्वच्छता है। जब तक हम स्रोत नियंत्रण यानी सोर्स रिडक्शन नहीं करते, तब तक मच्छरों को पूरी तरह नियंत्रित नहीं किया जा सकता। इसलिए सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया है कि वे लगातार सफाई अभियान चलाएं और समुदाय को भी इस प्रयास में भागीदार बनाएं।'

ब्लॉक स्तर पर माइक्रो प्लान तैयार

स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर राजेश कुमार ने बताया कि नगर निगमों व नगर निकायों को निर्देशित किया गया है कि वे नियमित रूप से सफाई अभियान, नाले-नालियों की सफाई, जलजमाव हटाने तथा कचरा निस्तारण पर जोर दें। सोर्स रिडक्शन के तहत आशा कार्यकर्ताओं की टीमों को प्रशिक्षित कर फील्ड में सक्रिय किया जाएगा जो घर-घर जाकर लोगों को जागरूक करेंगी। जरूरत के अनुसार फॉगिंग की कार्यवाही भी की जाएगी ताकि वयस्क मच्छरों का सफाया किया जा सके। जनजागरूकता अभियान के लिए हैंडबिल, पोस्टर, बैनर, नुक्कड़ नाटक, स्कूलों में गोष्ठियों जैसे IEC संसाधनों का भरपूर उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। सभी ब्लॉकों को माइक्रो प्लान तैयार कर राज्य एनवीबीडीसीपी यूनिट को भेजने के निर्देश दिए गए हैं।

अलग डेंगू वार्ड और संसाधनों की उपलब्धता

स्वास्थ्य सचिव डॉ आर राजेश कुमार ने बताया कि राज्य व निजी अस्पतालों में डेंगू व चिकनगुनिया रोगियों के इलाज के लिए भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार व्यवस्थाएं लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी जिलों में अलग डेंगू आइसोलेशन वार्ड स्थापित किए जाएंगे, जिनमें मच्छरदानी युक्त पर्याप्त संख्या में बेड, प्रशिक्षित चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ और जरूरी उपकरण मौजूद रहेंगे। गंभीर रोगियों (DHF/DSS) के लिए प्लेटलेट्स, ELISA जांच किट्स और अन्य औषधीय सामग्री की समय पर आपूर्ति अनिवार्य की गई है। फीवर सर्वेक्षण के जरिए संदिग्ध रोगियों की पहचान की जाएगी, और पॉजिटिव केस मिलने पर रोगी के घर से 50 मीटर की परिधि में स्पेस स्प्रे/फोकल स्प्रे की कार्रवाई की जाएगी। रैपिड रिस्पॉन्स टीम को हर जिले में अलर्ट मोड पर रखा गया है ताकि आपातकालीन स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके।

जन सहयोग और मीडिया की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण: वास्थ्य सचिव ने कहा कि, 'डेंगू और चिकनगुनिया से लड़ाई सिर्फ सरकार की नहीं, समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। जब तक आमजन तक सही जानकारी नहीं पहुंचेगी, तब तक रोकथाम के प्रयास अधूरे रहेंगे।' सभी जिलों में जनजागरूकता अभियान को शीर्ष प्राथमिकता दी जाएगी। आईएमए, निजी अस्पतालों, पैथोलॉजी लैब्स के साथ सीएमई बैठकें कर समन्वय स्थापित किया जाएगा ताकि भ्रांतियों को दूर किया जा सके। सभी जनपदों में एक मीडिया स्पोक्सपर्सन नियुक्त किया जाएगा जो सकारात्मक सूचना का संप्रेषण सुनिश्चित करेगा।

हेल्पलाइन और कंट्रोल रूम व्यवस्था होगी मजबूत: स्वास्थ्य सचिव ने बताया किराज्य मुख्यालय पर क्रियाशील हेल्पलाइन 104 को पूरी तरह से जनता के लिए सक्रिय रखा गया है ताकि कोई भी व्यक्ति अपनी शंका या समस्या को साझा कर सके और तत्काल सलाह प्राप्त कर सके। डेंगू के संक्रमण काल के दौरान सभी जनपदों में कंट्रोल रूम स्थापित किए जाएंगे और उनके नंबर राज्य एनवीबीडीसीपी यूनिट को उपलब्ध कराए जाएंगे। सभी जिलों को निर्देशित किया गया है कि वे हर दिन शाम 4 बजे तक दैनिक रिपोर्टिंग सुनिश्चित करें, चाहे कोई केस हो या न हो।

सभी विभाग निभाएं सक्रिय भूमिका: स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर राजेश कुमार ने बताया कि इस बार की कार्ययोजना में यह विशेष ध्यान दिया गया है कि केवल स्वास्थ्य विभाग ही नहीं, बल्कि अन्य विभाग भी जिम्मेदार भूमिका निभाएं। नगर विकास, पंचायती राज, जल संस्थान, विद्यालय शिक्षा, सूचना एवं जनसंपर्क जैसे विभागों को उनकी जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिससे डेंगू व चिकनगुनिया को रोकने के प्रयास सामूहिक रूप से मजबूत बनें।

पीडीए को मजबूत करने की रणनीति है अखिलेश का दलित प्रेम

अजय कुमार, लखनऊ

उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति का मिजाज लगातार बदल रहा है। बसपा के चुनावी रण में कमजोर पड़ते ही सभी दलों ने बीएसपी के कोर दलित वोटरों को अपने पाले में लाने के लिये बिसात बिछाना शुरू कर दी है। यह सिलसिला 2017 से शुरू हुआ था और अब चरम पर नजर आ रहा है। इसी का परिणाम है कि अब किसी भी चुनाव में दलित वोटों में भी बिखराव देखने को मिलता है। स्थिति यह कि मौजूदा राजनीति में महात्मा गांधी तो अप्रासंगिक हो गये हैं जबकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का 'सिक्का' चल रहा है। कांग्रेस जिसने गांधी के नाम के सहारे कई चुनाव जीते अब उसे भी बाबा साहब में अपना भविष्य नजर आता है। कुछ वोट बैंक के सौदागरों द्वारा बाबा साहब को ऐसा महिमामंडित कर दिया गया है मानों पूरा संविधान उन्हीं ने तैयार किया था। वोट बैंक की खातिर देश के संविधान को बाबा साहब का संविधान कहकर प्रचारित प्रसारित किया जाता है, जबकि हकीकत में राजनैतिक दलों की यह सब कसरत दलित वोटों के लिये है। यूपी में भाजपा और समाजवादी पार्टी आजकल दलितों के नये रहनुमा बनने में लगे हैं। यह इस लिये है क्योंकि यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं, और समाजवादी पार्टी (सपा) ने दलित समुदाय को अपने पक्ष में करने के लिए एक व्यापक रणनीति अपनाई है। पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) गठबंधन को केंद्र में रखते हुए दलित नेताओं को पार्टी में शामिल किया है और विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से दलित मतदाताओं तक पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं।

सपा ने 2022 के विधानसभा चुनावों में इंद्रजीत सरोज, त्रिभुवन दत्त, आर.के. चौधरी और राम प्रसाद चौधरी जैसे प्रमुख दलित नेताओं को पार्टी में शामिल किया था। अब इसमें नया नाम बसपा के पूर्व दलित नेता दद्दू प्रसाद का शामिल हो गया है। इन नेताओं को अब 2027 के चुनावों के लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं, ताकि वे अपने समुदाय के वोटों को सपा के पक्ष में मोड़ सकें। इसके अतिरिक्त, फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद को दलित चेहरे के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, जिन्हें अखिलेश यादव लगातार अपने साथ रख रहे हैं।

सपा ने पीडीए पर चर्चा नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका उद्देश्य पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समुदायों को भाजपा सरकार द्वारा उनके अधिकारों पर किए जा रहे हमलों और संविधान के साथ हो रहे खिलवाड़ के बारे में जागरूक करना है। इस कार्यक्रम के तहत पार्टी कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर पीडीए समुदाय के लोगों से संवाद कर रहे हैं और उन्हें सपा की नीतियों से अवगत करा रहे हैं। सपा ने दलित समुदाय के साथ अपनी एकजुटता दिखाने के लिए विभिन्न प्रतीकात्मक कदम उठाए हैं। लखनऊ में पार्टी कार्यालय के बाहर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, राम मनोहर लोहिया और हनुमान जी की तस्वीरों वाले होर्डिंग्स लगाए गए हैं, जिन पर हम दलितों के साथ हनुमान जी जैसे संदेश लिखे गए हैं। इसके अलावा, पार्टी ने अंबेडकर जयंती पर बड़े कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई है, ताकि दलित समुदाय के साथ अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत किया जा सके।

सपा ने 2024 के लोकसभा चुनावों में उम्मीदवार चयन में पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समुदायों को प्राथमिकता दी थी। पार्टी ने 57 उम्मीदवारों में से 15 अनुसूचित जाति, 29 पिछड़े वर्ग और 4 मुस्लिम समुदाय से उम्मीदवार उतारे थे। इस संतुलन को 2027 के विधानसभा चुनावों में भी बनाए रखने की योजना है, ताकि पीडीए गठबंधन को और मजबूत किया जा सके। इसी क्रम में अखिलेश यादव भाजपा सरकार पर दलितों और आदिवासियों को निशाना बनाने का आरोप लगाते हैं। वह कहते हैं कि भाजपा सरकार पीडीए समुदाय के लोगों की नियुक्ति रोक रही है और उनके अधिकारों को छीन रही है। अखिलेश ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा सरकार संविधान और आरक्षण के साथ खिलवाड़ कर रही है, और उन्होंने पीडीए समुदाय से भाजपा को सत्ता से बाहर करने का आहवान किया है।

लब्बोलुआब यह है कि समाजवादी पार्टी ने 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए दलित समुदाय को अपने पक्ष में करने के लिए एक व्यापक रणनीति अपनाई है। पार्टी ने दलित नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी हैं, पीडीए पर चर्चा कार्यक्रम शुरू किया है, प्रतीकात्मक कदम उठाए हैं, उम्मीदवार चयन में संतुलन बनाए रखा है, और भाजपा पर तीखे आरोप लगाए हैं। 14 अप्रैल को बाबा साहब की 150 जयंती के समय भी समाजवादी पार्टी ने पूरे प्रदेश में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया। अखिलेश यादव ने लखन में बाबा साहब की मूर्ति पर पुष्प चढ़ाकर उनके नमन किया। अखिलेश के इन सभी प्रयासों का उद्देश्य दलित समुदाय के समर्थन को हासिल करना और 2027 के चुनावों में भाजपा को सत्ता से बाहर करना है।

धामी सरकार देवभूमि के किसानों को बनाएगी 'मालामाल'

राज्य के कई जिलों में अब धामी सरकार किसानों को हाईटेक और मॉडर्न बनाने के लिए कमर कर चुकी है। बाजारों में फलों की दुकान पर बिकने वाला कीवी की राज्य में भी पैदावार होगी। यह फल किसानों को मालामाल करेगा। अब राज्य को मिलेट्स पॉलिसी, कीवी पॉलिसी और ड्रैगन फ्रूट पैदा करने के लिए पहचाना जाएगा। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि उत्तराखंड स्टेट मिलेट्स पॉलिसी के तहत दो चरणों में कार्य किया जाएगा। पहला चरण में 24 विकासखंडों में 30000 हेक्टेयर क्षेत्रफल रखा गया है। जो की 2025-26 से 2027-28 तक रहेगा। जबकि दूसरे चरण में 44 विकासखंडों में 40000 हेक्टर क्षेत्रफल रहेगा जो 2028-29 से 2030-31 तक रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि मिलेट पॉलिसी प्रदेश के 11 जिलों में लागू होगी। जिसके लिए कुल 134.89 करोड़ की कार्ययोजना का संचालन किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों को परंपरागत खेती के बजाय नकदी फसल उगाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है।

देवभूमि के किसान जल्द ही नकदी फसल उगाते हुए नजर आएंगे। राजधानी देहरादून से लेकर राज्य के कई जिलों में अब धामी सरकार किसानों को हाईटेक और मॉडर्न बनाने के लिए कमर कर चुकी है। बाजारों में फलों की दुकान पर बिकने वाला कीवी की राज्य में भी पैदावार होगी। यह फल किसानों को मालामाल करेगा। चार-पांच साल पहले देश में कोविद-19 के समय कीवी फल की पूरे देश भर में जबरदस्त डिमांड शुरू हुई थी। यह फल प्लेटलेट्स बढ़ाने में भी काफी फायदेमंद माना जाता है। राजधानी देहरादून को पूरे देश भर में लीची के लिए जाना जाता है अब राज्य को मिलेट्स पॉलिसी, कीवी पॉलिसी और ड्रैगन फ्रूट पैदा करने के लिए पहचाना जाएगा। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि उत्तराखंड स्टेट मिलेट्स पॉलिसी के तहत दो चरणों में कार्य किया जाएगा। पहला चरण में 24 विकासखंडों में 30000 हेक्टेयर क्षेत्रफल रखा गया है। जो की 2025-26 से 2027-28 तक रहेगा। जबकि दूसरे चरण में 44 विकासखंडों में 40000 हेक्टर क्षेत्रफल रहेगा जो 2028-29 से 2030-31 तक रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि मिलेट पॉलिसी प्रदेश के 11 जिलों में लागू होगी। जिसके लिए कुल 134.89 करोड़ की कार्ययोजना का संचालन किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों को परंपरागत खेती के बजाय नकदी फसल उगाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसी क्रम में राज्य कैबिनेट ने बीते दिनों मिलेट्स पॉलिसी, कीवी पॉलिसी और ड्रैगन फ्रूट की खेती की योजना पर मुहर लगाई है, जिसमें कुल मिलाकर 3 लाख 17 हजार से अधिक किसान लाभान्वित होंगे। उत्तराखण्ड स्टेट मिलेट्स पॉलिसी के तहत राज्य सरकार ने 2030-31 तक 11 पर्वतीय जिलों के लिए कुल 134.89 करोड़ रुपए की कार्ययोजना पर मुहर लगाई है। इसमें मंडुआ, झंगोरा, रामदाना, चीना एवं कौणी उत्पादक किसानों को बीज एवं जैव उर्वरक पर 80 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा, साथ ही कृषकों को मिलेट की बुवाई करने पर पंक्ति बुवाई पर रु0 4000 प्रति हेक्टेयर और सीधी बुवाई पर रु0 2000 प्रति हेक्टेयर की प्रोत्साहन धनराशि दी जायेगी। मिलेट पॉलिसी के तहत प्रत्येक वर्ष विकासखण्ड स्तर पर उत्कृष्ट कार्य के लिए 02 कृषक / समूह को पुरस्कार दिया जायेगा। साथ ही प्रत्येक विकासखण्ड स्तर पर 01 मिलेट प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की जायेगी। योजना के तहत 3 लाख से अधिक किसानों को लाभ देने का लक्ष्य है।

धामी सरकार श्रीअन्न फूड पार्क की स्थापना भी करेगी

धामी सरकार इसके तहत श्रीअन्न फूड पार्क की स्थापना भी करेगी। इसी तरह उत्तराखण्ड कीवी पॉलिसी के तहत वर्ष 2030-31 तक राज्य सरकार कीवी उद्यान स्थापना के लिए कुल लागत 12 लाख प्रति एकड़ का 70 प्रतिशत राजसहायता प्रदान करेगी। जिसमें 30 प्रतिशत लाभार्थी का अंश होगा। यह नीति भी हरिद्वार एवं ऊधमसिंह नगर को छोड़कर राज्य के शेष 11 जनपदों में लागू होगी। कीवी पॉलिसी के अन्तर्गत कुल 894 करोड़ की कार्ययोजना तैयार की गई है, नीति के तहत 3500 हेक्टेयर क्षेत्रफल को आच्छादित किए जाने का लक्ष्य है, जिसमें करीब 17,500 किसान लाभान्वित होंगे। अभी राज्य के लगभग 683 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 382 मीट्रिक टन कीवी का उत्पादन किया जा रहा है। इसी तरह ड्रैगन फ्रूट खेती योजना के अंतर्गत ऊधमसिंह नगर, हरिद्वार, नैनीताल, बागेश्वर, पौड़ी, देहरादून, टिहरी में ड्रैगन फ्रूट के उत्पादन को आधुनिक / वैज्ञानिक पद्यति के माध्यम से बढ़ावा दिया जाएगा। योजना के तहत वर्ष 2027-28 तक 15 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च की जाएगी। जिससे 450 किसान लाभान्वित होंगे। प्रस्तावित योजना में उद्यान स्थापना के लिए 08 लाख प्रति एकड़ पर 80 प्रतिशत राजसहायता का प्राविधान है एवं शेष 20 प्रतिशत कृषक द्वारा वहन किया जाएगा। वर्तमान में राज्य के लगभग 35 एकड़ क्षेत्रफल में 70 मीट्रिक टन ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन किया जा रहा है।

पूर्व राज्यपाल के बेटे होंगे देश के नए मुख्य न्यायाधीश

बीआर गवई देश के नए मुख्य न्यायाधीश होंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने आधिकारिक तौर पर जस्टिस गवई को अपना उत्तराधिकारी बनाने की सिफारिश की है। उनके नाम को मंजूरी के लिए केंद्रीय कानून मंत्रालय को भेज दिया है। वह 14 मई को शपथ लेंगे। बीआर गवई अनुसूचित जाति से आने वाले दूसरे चीफ जस्टिस होंगे, उनके पहले सीजेआई केजी बालाकृष्णन भी अनुसूचित जाति के थे। उनके पिता दिवंगत आरएस गवई एक राजनेता थे। उन्होंने महाराष्ट्र में राजनीति करने के लिए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (गवई) नाम की पार्टी बनाई थी। वे आरएस गवई के बेटे हैं जो बिहार और केरल के राज्यपाल रह चुके हैं।

भूषण रामकृष्ण (बीआर) गवई देश के नए मुख्य न्यायाधीश होंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने आधिकारिक तौर पर जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई को अपना उत्तराधिकारी बनाने की सिफारिश की है। उनके नाम को मंजूरी के लिए केंद्रीय कानून मंत्रालय को भेज दिया है। इस सिफारिश से जस्टिस गवई के भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बनने का रास्ता साफ हो गया है। वह 14 मई को शपथ लेंगे। वर्तमान सीजेआई संजीव खन्ना ने बुधवार को केंद्रीय कानून मंत्रालय से सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश बीआर गवई को अगला सीजेआई नियुक्त करने की सिफारिश की थी। सीजेआई खन्ना 13 मई को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। बीआर गवई अनुसूचित जाति से आने वाले दूसरे चीफ जस्टिस होंगे, उनके पहले सीजेआई केजी बालाकृष्णन भी अनुसूचित जाति के थे। उनके पिता दिवंगत आरएस गवई एक राजनेता थे। उन्होंने महाराष्ट्र में राजनीति करने के लिए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (गवई) नाम की पार्टी बनाई थी। वे आरएस गवई के बेटे हैं जो बिहार और केरल के राज्यपाल रह चुके हैं। परंपरा के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस ही अपने उत्तराधिकारी का नाम सरकार को भेजते हैं। इस बार भी यही प्रक्रिया अपनाई गई है। कानून मंत्रायल ने औपचारिक तौर पर जस्टिस खन्ना से उनके उत्तराधिकारी का नाम पूछा था, जिसके जवाब में उन्होंने जस्टिस गवई का नाम आगे बढ़ाया।

बीआर गवई का कार्यकाल छह महीने से अधिक का होगा

52वें सीजेआई बनने की दौड़ में शामिल न्यायमूर्ति गवई का कार्यकाल 6 महीने से अधिक का होगा और वे 23 नवंबर, 2025 को पद से मुक्त होंगे। सीजेआई खन्ना ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर न्यायमूर्ति गवई के नाम की सिफारिश की है, जो

सीजेआई द्वारा अपने उत्तराधिकारी के रूप में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को नामित करने की स्थापित परंपरा के अनुसार है। मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के अनुसार, केंद्र निवर्तमान सीजेआई से सेवानिवृत्ति से ठीक एक महीने पहले उत्तराधिकारी का नाम बताने के लिए कहता है। बेंच में पदोन्नत होने से पहले, उन्होंने संवैधानिक कानून और प्रशासनिक कानून में प्रैक्टिस की और नागपुर नगर निगम, अमरावती नगर निगम और अमरावती विश्वविद्यालय के लिए स्थायी वकील के रूप में कार्य किया। उन्हें अगस्त 1992 में बॉम्बे उच्च न्यायालय, नागपुर पीठ में सहायक सरकारी वकील और अतिरिक्त लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया गया जहां उन्होंने जुलाई 1993 तक सेवा की। उन्हें 17 जनवरी, 2000 को नागपुर पीठ के लिए सरकारी वकील और लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया गया था।

जस्टिस गवई का जन्म 24 नवंबर 1960 को महाराष्ट्र के अमरावती में हुआ

जस्टिस गवई का जन्म 24 नवंबर 1960 को महाराष्ट्र के अमरावती में हुआ था। जस्टिस गवई ने अपने वकालत करियर की शुरुआत साल 2003 में बॉम्बे उच्च न्यायालय में बतौर एडिशनल जज की थी। इसके बाद साल 2005 में वे स्थायी जज नियुक्त हुए। जस्टिस गवई ने 15 वर्षों तक मुंबई, नागपुर, औरंगाबाद और पणजी की पीठ में अपनी सेवाएं दीं। जस्टिस गवई के नाम पर अगर मुहर लगती है तो वे देश के दूसरे अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाले मुख्य न्यायाधीश होंगे। उनसे पहले जस्टिस केजी बालाकृष्णन साल 2010 में यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। जस्टिस बीआर गवई साल 2016 में नोटबंदी को लेकर दिए गए फैसले का हिस्सा रहे। जिसमें कहा गया था कि सरकार को करेंसी को अवैध घोषित करने का अधिकार है। इसके अलावा जस्टिस गवई बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ दिए आदेश का भी हिस्सा रहे और इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर फैसला देने वाली पीठ का भी हिस्सा रहे।

मोदी सरकार मे हुआ बाबा साहब का सही सम्मानः डॉ. नरेश बंसल

भाजपा राष्ट्रीय सह-कोषाध्यक्ष व सासंद राज्यसभा डा. नरेश बंसल ने संविधान शिल्पी भारत रत्न आदरणीय बाबासाहब डा. भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती पर नई दिल्ली मे आयोजित विभिन्न कार्यक्रम मे भाग लेते हुए बाबा साहब को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए व नमन किया।

डा. नरेश बंसल ने संसद के संविधान सदन व संसद परिसर मे प्रेरणा स्थल पर समाज एवं कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम मे भी बाबा साहब के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। ज्ञात को युक्त कार्यक्रम मे महामहिम राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, उपराष्ट्रपति जी, लोकसभा के सभापति जी समेत तमाम गणमान्य सांसदगण, केंद्रीय मंत्रीगण ने प्रतिभाग किया।

इससे पुर्व कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ़ इंडिया, नई दिल्ली मे भारतीय नमो संघ द्वारा आयोजित कार्यक्रम मे मुख्य अतिथि के रूप मे प्रतिभाग कर बाबा साहब अंबेडकर को श्रद्धांजली दी व उत्कृष्ट कार्य के लिए संस्थाओ व व्यक्तियो को सम्मानित किया। इसके बाद अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर मे भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा आयोजित कार्यक्रम मे डा. नरेश बंसल ने भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी,दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी,केंद्रीय मंत्री डा. बीरेन्द्र कुमार जी आदी महानुभावो के साथ बाबा साहब की प्रतिमा पर दीप जलाए व पुष्प अर्पित किए।

डा. नरेश बंसल ने कहा कि आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है। मैं बाबा साहब की स्मृतियों को नमन करता हूं। बाबा साहब ने इस देश को संविधान देकर वंचित वर्ग को जीविकोपार्जन की सारी सुविधाएं देने की संवैधानिक व्यवस्था दी है। बाबा साहब की सोच के अनुरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के वंचित वर्ग को योजनाएं देने का काम किया है। डा. नरेश बंसल ने कहा कि आदरणीय प्रधानसेवक नरेंद्र भाई मोदी जी ने भी कहा है कि उनकी प्रेरणा से ही आज देश सामाजिक न्याय के सपने को साकार करने में समर्पित भाव से लगा हुआ है। उनके सिद्धांत और आदर्श एक 'आत्मनिर्भर' और 'विकसित' भारत के निर्माण को शक्ति और गति देंगे। मोदी सरकार संविधान पर चलते हुए भारत को विकसित राष्ट्र बनाने को संकल्प बद्ध है।

डा. नरेश बंसल ने कहा कि डॉ. भीमराव अंबेडकर जी का जीवन भारत में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना को समर्पित था। उनके सम्मान और याद में 14 अप्रैल को पूरे देश में अंबेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है। महान समाज सुधारक अंबेडकर ने दलितों के अधिकारों के लिए जीवनभर संघर्ष किया। उन्होंने 'शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो' का नारा दिया।

डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर का संघर्ष, दलितों के उत्थान के लिए उनके प्रयास और आजाद भारत के संविधान के निर्माण में उनका योगदान बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। डॉ. अंबेडकर सिर्फ संविधान निर्माता नहीं थे, बल्कि वे सामाजिक न्याय, समानता और सम्मान के प्रतीक हैं।

डा. नरेश बंसल ने कहा कि कांग्रेस ने आंबेडकर का अंतिम संस्कार दिल्ली में नहीं होने दिया था। इस पुरानी पार्टी ने भारतीय संविधान के निर्माता का स्मारक बनाने से मना कर दिया था। इन्हीं लोगों ने बाबा साहब आंबेडकर को चुनाव हारने दिया। उनके 'महा परिनिर्वाण' के बाद स्मारक भी नहीं बनने दिया।

मुख्य सचिव ने की कुंभ 2027 की तैयारियों की समीक्षा

एक सप्ताह में नोडल अधिकारी करें नामितः मुख्य सचिव

मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय में कुंभ 2027 की तैयारियों के सम्बन्ध में बैठक आयोजित हुई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को कुंभ 2027 की तैयारियों के लिए सभी सम्बन्धित विभागों योजना एवं प्रस्ताव तैयार किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने जिलाधिकारी हरिद्वार को सम्बन्धित विभागों के साथ शीघ्र बैठक आयोजित किए जाने की के निर्देश दिए।

एक सप्ताह में पद सृजन और नोडल अधिकारी करें नामितः मुख्य सचिव

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि अगले 7 दिनों में सभी कार्यदायी विभागों के नोडल अधिकारी नामित कर लिए जाएं। साथ ही, पदों के सृजन की कार्यवाही भी पूर्ण कर ली जाए। इनसे सम्बन्धित आदेश अगले 7 दिनों में कर लिए जाएं। उन्होंने कहा कि जिन समितियों/ उप समितियों का गठन किया जाना है, अगले 7 दिनों में कर लिया जाए। उन्होंने 30 अप्रैल तक प्रस्ताव एवं आंकलन तैयार कर भारत सरकार को भेजे जाने के भी निर्देश दिए।

मुख्य पर्वों के लिए क्राउड मैनेजमेंट और ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान किया जाए तैयार

मुख्य सचिव ने कुंभ 2027 के अंतर्गत शाही स्नान वाले विशेष दिवसों पर श्रद्धालुओं की अधिकतम संख्या का आंकलन करते हुए कार्य योजना तैयार किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में कनेक्टिविटी बढ़ने श्रद्धालुओं के बढ़ने की अत्यधिक सम्भावना है। उन्होंने इसके अनुरूप श्रद्धालुओं संख्या का आंकलन करते हुए पार्किंग एवं ट्रैफिक मूवमेंट योजना तैयार किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने इसके लिए विशेषज्ञों द्वारा आंकलन कराए जाने के उपरांत योजनाएं तैयार कराए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने नए पार्किंग स्थल चिन्हित किए जाने के साथ ही पुराने पार्किंग स्थलों की क्षमता बढ़ाए जाने के भी निर्देश दिए।

हरिद्वार क्षेत्र में ऑडिटोरियम और सांस्कृतिक केंद्र बनाए जाने के निर्देश

मुख्य सचिव ने कहा कि हरिद्वार कुंभ मेला, कांवड़ यात्रा एवं अन्य धार्मिक आयोजनों के लिए अत्यधिक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है, इसके लिए मूलभूत ढांचों को मजबूत किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि दीर्घकालीन योजना के अंतर्गत स्थाई प्रकृति के कार्यों को ध्यान में रखा जाए। उन्होंने हरिद्वार क्षेत्र में ऑडिटोरियम और सांस्कृतिक केंद्र बनाए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को कुंभ क्षेत्र सहित अन्य उपयोगी स्थानों का स्थलीय निरीक्षण कर कार्य योजनाएं तैयार किए जाने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने कुंभ 2027 के लिए अनिवार्य कार्यों की सूची तैयार किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा ऐसे कार्य जिन्हें अनिवार्य रूप से कराया जाना है, उनकी तैयारी पूर्व से ही कर ली जाए। साथ ही, तत्काल शुरू किए जाने वाले कार्यों की सूची भी तैयार कर इनकी डीपीआर एवं आंकलन सहित अन्य तैयारियां पूर्व में ही सुनिश्चित कर ली जाएं, ताकि स्वीकृति मिलते ही कार्य शुरू कराए जा सकें।

इस अवसर पर प्रमुख सचिव श्री आर. के. सुधांशु, श्री आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव श्री नीतेश झा, श्रीमती राधिका झा, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, श्री विनय शंकर पाण्डेय, श्री आर. राजेश कुमार, जिलाधिकारी हरिद्वार श्री कर्मेंद्र सिंह, जिलाधिकारी पौड़ी श्री आशीष चौहान, जिलाधिकारी टिहरी सहित सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

राज्य में 16 लाख स्मार्ट मीटर लगाकर टेक्नॉलोजी के माध्यम से पारदर्शिता लाने का हुआ कार्य

उत्तराखण्ड विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने मुख्यमंत्री का किया आभार व्यक्त

इकॉनोमी और इकॉलोजी के बीच समन्वय बनाकर ग्रीन एनर्जी के उत्पादन को दिया जा रहा प्रोत्साहन

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन, देहरादून में ऊर्जा निगमों के कार्मिकों द्वारा आयोजित 'स्वागत एवं अभिनन्दन' कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। उत्तराखण्ड विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा द्वारा ऊर्जा निगमों के कार्मिकों की विभिन्न समस्याओं के समाधान करने पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया गया।

मुख्यमंत्री ने सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस अभिनंदन की असली हकदार उत्तराखंड प्रदेश की जनता है, जिन्होंने प्रदेश की सेवा करने का अवसर दिया। उन्होंने कहा कि ऊर्जा प्रदेश उत्तराखंड की मूल अवधारणा में था। उत्तराखण्ड को पॉवर सरप्लस राज्य बनाने के लिए सबको समन्वय के साथ आगे बढ़ना होगा।। मुख्यमंत्री ने कहा भारत सरकार का राज्य सरकार को हर योजना पर सहयोग मिल रहा है। विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी रैंकिंग में यूपीसीएल ने विशेष श्रेणी डिस्कॉम में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार, उत्तराखण्ड को ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए संकल्पित है। बिजली उत्पादन के लिए लखवाड़ बांध परियोजना, जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना और देहरादून में आने वाले 50 सालों में पेयजल की समस्याओं को दूर करने के लिए सौंग बांध परियोजना पर कार्य गतिमान है। राज्य में अत्याधुनिक जीआईएस द्धगैस इंसुलेटेड सबस्टेशनत्रः उपकेंद्रों की स्थापना भी जारी है। उन्होंने कहा राज्य में 16 लाख स्मार्ट मीटर लगाकर टेक्नॉलजी के माध्यम से पारदर्शिता लाने का कार्य किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरादून शहर की बिजली लाइनें भूमिगत की जा रही हैं। यूपीसीएल द्वारा अत्याधुनिक ओटोमेटेड डिमान्ड रिसपॉन्स सिस्टम के उपयोग से ओवरड्राल की स्थिति पर रियल टाइम पर नियंत्रण कर हर वर्ष करोड़ो रूपये की बचत की है। उन्होंने कहा 2023 में देहरादून में श्विव स्तरीय आपदा प्रबंधन सम्मलेन आयोजित किया गया था। आपदाओं को रोका नहीं जा सकता पर आपदाओं के प्रभाव को कम किया जा सकता राज्य सरकार ने इकोलॉजी और इकोनॉमी में संतुलन वाले विकास के मॉडल को चुना है। इकॉनमी और इकॉलजी के बीच समन्वय बनाकर ग्रीन एनजह्व के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अन्तर्गत लगभग 20,000 रूफटॉप सोलर संयंत्र किए गए स्थापित। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों की बेस्ट प्रैक्टिस को हमने अपने राज्य में भी अपनाना है। राज्य सरकार आने वाले 10 , 25, 50 सालों को देखते हुए भी विकास के मॉडल तैयार कर रही है।

इस अवसर पर प्रमुख सचिव श्रीआर मीनाक्षी सुंदरम, एम.डी यू.जे.वी.एन.एल श्री संदीप सिंघल और उत्तराखंड विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के पदाधिकारी उपस्थित थे।

एनडीए 154 कोर्स में एक बार फिर डीडीए डायमंड्स का जलवा बरकरार

डीडीए की परंपरा के मुताबिक सफल छात्रों को मिलेंगे 10-10 हजार रूपये नगद

यूपीएससी द्वारा 01 सितंबर 2024 को हुए एनडीए एग्जाम की फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। इस एनडीए 154 की मेरिट लिस्ट में डीडीए डायमंड्स की सफलता ने एक बार फिर डीडीए की विश्वसनीयता को सिद्ध किया है।

सहसत्रधारा रोड स्थित दून डिफेंस एकेडमी के डीडीए डायमंड्स ने इस सफलता का पूरा श्रेय दून डिफेंस एकेडमी के निदेशक संदीप गुप्ता द्वारा दिए गए सही मार्ग दर्शन को देते हुए कहा कि डीडीए की बेस्ट फेकल्टी, स्टडी मेटेरियल की बदौलत वे अपने लक्ष्य को हासिल कर पाए। डीडीए के निदेशक संदीप गुप्ता ने परीक्षा पास पास करने वाले छात्रों को बधाई देते हुए कहा कि अब देश के प्रति आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई हैं। उन्होंने कहा कि एक अच्छा अधिकारी बनने के साथ जिम्मेदार नागरिक भी बनना है।

वहीं डीडीए की परंपरा के मुताबिक एनडीए 154 कोर्स की मेरिट लिस्ट में जगह बनाने वाले सभी डीडीए डायमंड्स को आशीर्वाद के रूप में 10-10 हजार रूपये नगद दिए जायेंगे।

एनडीए 154 कोर्स को मेरिट में जगह बनाने वाले डीडीए डायमंड्स में निहारिका (गर्ल्स एआइआर 26), श्री (एआइआर 607), अर्णव मेनन (एआइआर 143), अभिनव खत्री (एआइआर 92), युवराज (एआइआर 546), सात्विक (एआइआर 153), निखिल यादव (एआइआर 589) व मेहर प्रतिक (एआइआर 593) हैं।

डॉ. दिनेश बर्तवाल प्रधानाचार्य दून इंटरनेशनल स्कूल को उत्कृष्ट शिक्षक मार्गदर्शक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया

देहरादून में आयोजित एक भव्य समारोह में मुख्य अतिथि डॉ. मुकुल सती जी, निदेशक शिक्षा, उत्तराखंड सरकार और विशिष्ट अतिथि श्री वी के धुंडियाल जी, मुख्य शिक्षा अधिकारी, देहरादून श्री निघिल एन, अकादमिक मेंटर अमृता विश्व विद्यापीठम, डॉ. आर पी गुप्ता और डॉ. हेमचंद जी द्वारा सयुंक्त रूप से डॉ. दिनेश बर्तवाल ,प्रधानाचार्य ,दून इंटरनेशनल स्कूल सिटी कैम्पस को प्रतिष्ठित उत्कृष्ट शिक्षक मार्गदर्शक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार अमृता विश्व विद्यापीठम और दैनिक जागरण आई-नेक्स्ट द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है, जो शिक्षा के क्षेत्र में असाधारण योगदान को मान्यता देने के साथ पुरस्कार प्राप्त प्रधानाचार्य, शिक्षकों को छात्र हित में और अधिक मेहनत करने की प्रेरणा देता है। यह शिक्षक उत्कृष्टता पुरस्कार उन प्राचार्यों व शिक्षकों को दिया जाता है जिन्होंने युवा दिमागों को आकार देने और दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए समर्पण दिखाया है। यह मान्यता पुरस्कार विजेता की असाधारण शिक्षण उत्कृष्टता और छात्रों को प्रेरित करने की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

डॉ. दिनेश बर्तवाल ने इस पुरस्कार के लिए अपने छात्रों, सहयोगी शिक्षकों और विधालय प्रबंधन प्रति आभार व्यक्त किया, और कहा कि यह मान्यता उन्हें शिक्षण उत्कृष्टता, युवा दिमागों को प्रेरित करने के लिए और अधिक प्रेरित करगी। डॉ. बर्तवाल द्वारा अमृता विश्व विद्यापीठम और दैनिक जागरण आई-नेक्स्ट को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के माध्यम से उत्कृष्ट प्रधानाचार्य, शिक्षकों को मान्यता देने के लिए धन्यवाद दिया गया।

उत्तराखंड की महिलाओं का प्रतिनिधित्व करेंगी कमलप्रीत- मनीषा अहलावत

कमल प्रीत रालोद महिला प्रकोष्ठ की नई अध्यक्ष और सरिता देवी को गढ़वाल की कमान

राष्ट्रीय लोकदल की उत्तराखंड में तेजी से विस्तार प्रक्रिया शुरू कर दी हैं। प्रदेश कार्यकारिणी, महानगर और जिले के बाद निर्माण के साथ-साथ प्रकोष्ठ खोलने की भी शुरुआत राष्ट्रीय लोकदल ने कर दी है। इसी क्रम में राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष मनीषा अहलावत ने उत्तराखंड प्रदेश की कमल प्रीत अरोरा को प्रदेश अध्यक्ष महिला और हरिद्वार की चौ. सरिता देवी को गढ़वाल अध्यक्ष नियुक्त कर अपना विश्वास जताया। मनीषा अहलावत ने अपने कथन में कहा कि 'जाटों की पार्टी माने जाने वाली रालोद अपने नेता श्री जयंत जी के दिखाए सर्वसामाज के अपने सन्देश को मजबूती से जनता के बीच ला रही है।'

कमल प्रीत ने राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार जताया और कहा कि वो प्रदेश में रालोद को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगी। कमल पिछले 20 सालों से सामाजिक कार्यों को करते हुए कई सम्मान प्राप्त कर चुकी हैं। इतना ही नहीं उनका नाम अल्पसंख्यक समुदाय में बड़े आदर से लिया जाता है और वर्तमान सरकार में भी उनके अल्पसंख्यक आयोग का हिस्सा बनने की भी अटकलें लगाई जा रही हैं। यूं तो महिला प्रकोष्ठ के लिए कई दावेदार नज़र आये पर अपने बेहतरीन कामों और सरल स्वभाव होने का पूरा फायदा यहाँ कमल प्रीत को मिला सबको पीछे छोड़ अभी कुछ समय पहले ही रालोद का दामन थामने वाली कमल अब प्रदेश की महिलाओं का नेतृत्व करेंगीं।

राष्ट्रीय अध्यक्षा महिला प्रकोष्ठ मनीषा अहलावत ने कमल प्रीत को शुभकामनायें देते हुए उन्हें उत्तराखंड की महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने का मंत्र दिया जैसा कि विदित है रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंती सिंह चौधरी सरकार का हिस्सा होते हुए कौशल विभाग के कैबिनेट मंत्री हैं और उत्तराखंड में रोजगार की बड़ी संभावनाएं मौजूद हैं। इन सब को देखते हुए और कमलप्रीत के सामाजिक कामों को देखा जाए तो लगता है राष्ट्रीय लोकदल उत्तराखंड महिलाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने में अवश्य कामयाब होगा।

इस अवसर पर मुख्य प्रवक्ता अनुपम खत्री ने मीडिया से बात करते हुए करते हुए बताया कि 'कमलप्रीत के अध्यक्ष बनने पर दल के प्रदेश अध्यक्ष सहित सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने कमलप्रीत को बहुत शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए राष्ट्रीय नेतृत्व के फैसले पर आभार जताया है।'

20 जनवरी, 2025 को विश्वविद्यालय की स्थापना के 20वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय की कॉफी टेबल बुक का विमोचन माननीय राज्यपाल उत्तराखंड द्वारा शुक्रवार, 11 अप्रैल, 2025 को राजभवन, देहरादून में किया गया।

जानिए कैसा होगा आपका यह सप्ताह

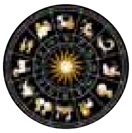

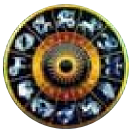

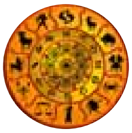

पं. दीपक प्रसाद, शास्त्री (मो. 9557730042)
(ज्योतिष, कर्मकाण्ड, धर्मिक अनुष्ठान आदि)

मेष राशि- जायदाद से संबंधित रुका मामला हल हो सकता है। खर्चे ज्यादा रहेंगे। नकारात्मक लोग आपके कार्यों में बाधा डालने का प्रयास कर सकते हैं। बेहतर होगा कि ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखें। आयात-निर्यात से जुड़े व्यवसायों में फायदेमंद एग्रीमेंट मिल सकते हैं। हालांकि, संपत्ति से संबंधित किसी सौदे के दौरान कागजी कार्यवाही को बहुत सावधानी से करें।

वृषभ राशि- पारिवारिक रखरखाव और सुधार से संबंधित कार्यों में समय सुखद बीतेगा। परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठकर अपने विचार साझा करेंगे। केवल कल्पनाओं में न जीएं, बल्कि जीवन की वास्तविकताओं को समझें। व्यवसायिक गतिविधियों में अभी तत्काल सुधार की संभावना कम है, इसलिए कार्यप्रणाली में बदलाव करना जरूरी है।

मिथुन राशि- युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आयात-निर्यात से संबंधित व्यवसाय में निवेश करना लाभकारी रहेगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियों में कार्यरत लोग अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने में विशेष ध्यान दें। अपनी लापरवाही या आलस के कारण घर की व्यवस्था को प्रभावित न होने दें। जीवनसाथी को कोई उपहार देना न भूलें।

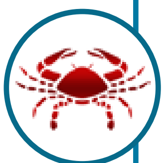

कर्क राशि- दूसरों पर अत्यधिक भरोसा करने के बजाय अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें। इस समय धन से संबंधित किसी भी प्रकार का लेन-देन करने से बचें। कार्यक्षेत्र में सुधार के लिए और अधिक विचार-मंथन की आवश्यकता है। अपनी मेहनत और कार्यक्षमता में कमी न आने दें। व्यवसाय को बढ़ाने के लिए अनुभवी व्यक्तियों का मार्गदर्शन अवश्य लें।

सिंह राशि- उच्च अधिकारियों और सम्मानित व्यक्तियों से संबंध बनाए रखना आपके व्यवसाय के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। उनके सहयोग से कोई बड़ा ऑर्डर या एग्रीमेंट मिल सकता है। नौकरीपेशा लोगों को वित्तीय कार्यों में विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। पति-पत्नी आपसी सामंजस्य से घर की व्यवस्था को बेहतर बनाए रखेंगे।

कन्या राशि- नए कार्य की शुरुआत भी हो सकती है। नौकरीपेशा लोग अपने अधिकारियों से संबंध मधुर रखें। प्रमोशन के योग बन रहे हैं। जीवनसाथी और परिवारजनों का उचित सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंधों में किसी तीसरे व्यक्ति के कारण गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है। अत्यधिक प्रदूषण और भीड़भाड़ वाली जगहों से बचें, क्योंकि त्वचा से संबंधित एलर्जी की आशंका है।

तुला राशि- व्यवसाय से संबंधित कोई महत्वपूर्ण यात्रा लाभकारी सिद्ध होगी। जोखिम लेना व्यवसाय में फायदेमंद हो सकता है। नौकरी में बदलाव की इच्छा रखने वालों को कोई शुभ समाचार मिल सकता है। परिवार में किसी समस्या को लेकर विचार-विमर्श होगा, और उचित समाधान भी निकलेगा। विवाह योग्य लोगों के लिए अच्छा रिश्ता आ सकता है।

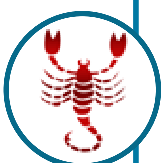

वृश्चिक राशि- पारिवारिक विवादों का समाधान होने से घर में शांति और सुकून का माहौल रहेगा। इससे आप अपनी व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक ध्यान दे पाएंगे। किसी नजदीकी मित्र का सहयोग आपके मनोबल और आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। संतान की शिक्षा से संबंधित कार्यों में अधिक भागदौड़ रहेगी, लेकिन यह प्रयास अंततः सार्थक सिद्ध होगा।

धनु राशि- अध्ययन और अध्यापन से संबंधित कार्यों में रुचि रहेगी। सामाजिक गतिविधियों में भी आप बढ़-चढ़कर हिस्सा लेंगे। भाई-बहनों के साथ संबंधों में कुछ तनाव उत्पन्न हो सकता है। अपनी वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखें, अन्यथा बना हुआ कार्य बिगड़ सकता है। कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। बुद्धिमत्ता और चतुराई से व्यापार में लाभ होगा।

मकर राशि- अत्यधिक जिम्मेदारियां लेने से आपकी मानसिक शांति भंग हो सकती है। आपकी उपलब्धियों के कारण कुछ लोग आपके प्रति ईर्ष्या की भावना रख सकते हैं। इन सबको नजरअंदाज कर अपने कार्यों पर ध्यान दें। मीडिया और ऑनलाइन गतिविधियों से जुड़े व्यवसाय फायदे की स्थिति में रहेंगे। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत के अनुरूप उचित परिणाम प्राप्त होंगे।

कुंभ राशि- विपरीत परिस्थितियों को धैर्य और शांति से अपने अनुकूल बनाएं। यदि भूमि से संबंधित कोई कार्य चल रहा है, तो कागजी कार्यवाही को लेकर कुछ गलतफहमी हो सकती है। विदेश से संबंधित व्यवसाय में कुछ अनुकूल परिस्थितियां बनने की संभावना है। परिवार में वरिष्ठ सदस्यों का मार्गदर्शन उचित व्यवस्था बनाए रखेगा। मित्रों से मुलाकात सुखद रहेगी।

मीन राशि- घर-परिवार के लिए भी कुछ समय अवश्य निकालें। धैर्य और समझदारी से कार्य करना आवश्यक है। मीडिया और ऑनलाइन गतिविधियों के माध्यम से नई व्यवसायिक जानकारी प्राप्त करें। नौकरीपेशा लोगों के लिए कार्यालय का माहौल अनुकूल रहेगा। वैवाहिक जीवन में गलतफहमी के कारण कुछ तनाव रह सकता है। शांतिपूर्ण तरीके से समस्याओं का समाधान करें।

परदे पर पहले ही दीन 'केसरी 2' ने 10 फिल्मों को दी शिकस्त

ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जलियांवाला बाग हत्याकांड मामले में केस लड़ने वाले सी शंकरन नायर पर आधारित फिल्म केसरी चैप्टर 2 सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म ने पहले ही बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कलेक्शन किया है। आलम यह है कि इस फिल्म ने इस साल रिलीज हुई कई फिल्मों के धूल चटा दी है। जानिए इस बारे में।

केसरी चैप्टर 2 फिल्मी गलियारों में इन दिनों केसरी चैप्टर 2 की धूम मची हुई है। अक्षय कुमार की इस मोस्ट अवेटेड फिल्म ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। इस धमाकेदार शुरुआत ने न सिर्फ फिल्म के निर्माताओं को राहत की सांस दी है, बल्कि अक्षय कुमार के लिए भी उम्मीद की एक नई किरण जगाई है, जो हाल के दिनों में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए थे।

केसरी चैप्टर 2 को लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्साह था। 2019 में आई अक्षय कुमार की फिल्म केसरी को दर्शकों ने खूब सराहा था। सारागढ़ी के ऐतिहासिक युद्ध पर आधारित इस फिल्म ने देशभक्ति के जज्बे को बड़े पर्दे पर बखूबी उतारा था। अब 'केसरी चैप्टर 2' एक नई वीर गाथा लेकर आई है जिसे क्रिटिक्स और दर्शक खूब सराह रहे हैं। फिल्म का कलेक्शन भी दमदार है।

केसरी चौप्टर 2 का ओपनिंग डे कलेक्शन

केसरी चैप्टर 2 को लेकर जिस तरह का बज बन रहा था, उससे अंदाजा लगाया जा रहा था कि फिल्म अच्छी ओपनिंग कर सकती है और हुआ भी ऐसा ही। इस फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर ठीक-ठाक शुरुआत की है। सैकनिल्क के अर्ली ट्रेड के मुताबिक, अक्षय कुमार स्टारर केसरी चौप्टर 2 ने पहले दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर करीब 7.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है जो भले ही स्काई फोर्स (15 करोड़) से आगे नहीं निकल पाया, लेकिन बाकियों की तुलना में इसकी कमाई अच्छी रही है।

आलम यह है कि अक्षय कुमार की केसरी चैप्टर 2 ने पहले ही दिन शानदार कमाई करते हुए कई बड़ी फिल्मों के ओपनिंग डे कलेक्शन को धूल चटा दी है। यहां देखिए उन फिल्मों की लिस्ट जिसे केसर चैप्टर 2 ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर पछाड़ दी है।

R.N.I.: UTTHIN/2010/41629 Postal Regd. UA/DO/DDN/01/2025-2027

धन्यवाद उत्तराखंड

सफल प्रकाशन का गौरवशाली 14वाँ वर्ष

उत्तराखंड से प्रकाशित एकमात्रा समाचार साप्ताहिक पत्रिका

दिव्य हिमगिरि

हिमालयी राज्यों की पहली साप्ताहिक पत्रिका

नज़र सब पर

मूल्यः रु 15/- मात्र

नए कलेवर में प्रत्येक रविवार

प्रत्येक रविवार

दिव्य हिमगिरि

संपादकीय कार्यालय : 6, म्युनिसिपल रोड, बाला हिसार स्कूल के सामने, डालनवाला देहरादून (उत्तराखंड)
मोबाइल : +91 8433456398, 9410353164
Email: divyahimgiriddn@gmail.com